

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14



राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 20 अक्टूबर, 1987/28 अक्टूबर, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला 2, 20 अक्टूबर, 1987

कमांक एल० एल० आर० (डी०) (6) 123/87-नॉजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 20 अक्टूबर, 1987 को राष्ट्रपति

2068

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्टूबर, 1987/28 अगस्त, 1909

महोदय द्वारा यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण विधेयक, 1987 (1987 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 1987 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 के रूप में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 28 अक्टूबर, 1987 को यथा अनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किराए के नियन्त्रण और बेदखली का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में है ।

(3) यह अधिनियम नवम्बर, 1971 के सत्रहवें दिन को प्रवृत्त होगा और उस दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, किन्तु—

(i) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) और (झ), धारा 4, धारा 5, धारा 15 की उप-धारा (2), धारा 17, धारा 30 की उप-धारा (3), धारा 34 और अनुसूची-I में अन्तर्विष्ट उपबन्ध नियत दिन को प्रवृत्त होंगे;

(ii) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ), धारा 15 की उप-धारा (1) और (3), धारा 16, धारा 27, धारा 28 और अनुसूची-II में अन्तर्विष्ट उपबन्ध उस दिन से प्रवृत्त होंगे और प्रवृत्त हुए गए समझे जाएंगे जिसको तत्स्थानी उपबन्ध हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (घ), धारा 14-अ, धारा 14-आ, धारा 23-अ और धारा 23-आ में अन्तःस्थापित किए गए थे;

(iii) हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1971 की धारा 4 और धारा 29 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, उस दिन से जिसको ये उक्त अधिनियम में, यथास्थिति, प्रतिस्थापित या अन्तःस्थापित किए गए थे, नियत दिन तक संगणित अवधि के दौरान, प्रवृत्त रहे समझे जाएंगे; और

(iv) धारा 35 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) “नियत दिन” से अगस्त, 1987 का अठारहवां दिन अभिप्रेत है;

(ख) “इमारत” से किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे वह वस्तुतः उस प्रयोजन

1971 का 23

1971 का 23

के लिए प्रयोग की जा रही हो या नहीं, किराये पर दी गई कोई इमारत या इमारत का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके साथ किराये पर दी गई कोई भूमि, गोदाम, उप-गृह या फर्नीचर है, किन्तु इसके अन्तर्गत होटल, होस्टल या छात्रावास में कमरा नहीं है;

(ग) "नियन्त्रक" से इस अधिनियम के अधीन नियन्त्रक के कृत्यों के पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "भू-स्वामी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय किसी इमारत या किराये पर दी गई भूमि का, चाहे अपने वास्ते या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, या उसके फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासी, संरक्षक, रिसीवर, निष्पादक या प्रशासक के रूप में किराया प्राप्त करने का हकदार है और इसके अन्तर्गत ऐसा किराएदार जो किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि को, इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत रीति में शिकमी पट्टे पर देता है, विनिदिष्ट भू-स्वामी, और समय-समय पर भू-स्वामी के अधीन हक प्राप्त करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति है;

(ङ) "अनिवासीय इमारत" से कोई ऐसी इमारत अभिप्रेत है जो—

(i) मुख्यतः कारबार, या व्यापार के प्रयोजन के लिए; या

(ii) अंशतः कारबार या व्यापार के प्रयोजन के लिए और अंशतः निवास के प्रयोजन के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि जो व्यक्ति इमारत में कारबार या व्यापार करता है, उसमें निवास रखता है :

परन्तु यदि कोई इमारत एक से अधिक व्यक्तियों को अलग-अलग, निवास और अनिवासीय प्रयोजन के लिए किराए पर दी गई हो, तो उसका निवास के प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया भाग, अनिवासीय इमारत के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—जहां कोई इमारत मुख्यतः कारबार या व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यह अनिवासीय इमारत समझी जाएगी, चाहे उसका थोड़ा सा भाग निवास के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता हो;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "किराए पर दी गई भूमि" से मुख्यतः कारबार या व्यापार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए, अलग-अलग किराए पर दी गई भूमि अभिप्रेत है ;

(ज) "निवासीय इमारत" से कोई ऐसी इमारत अभिप्रेत है जो अनिवासीय इमारत नहीं है;

(झ) "विनिदिष्ट भू-स्वामी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने वास्ते किसी इमारत की बाबत किराया प्राप्त करने का हकदार है और जो संघ या राज्य के कार्यकलाप से सम्बद्ध लोक सेवा में किसी पद पर नियुक्ति धारण कर रहा है या धारण की है;

(ञ) "किराएदार" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिस द्वारा या जिसकी ओर से इमारत या किराए पर दी गई भूमि के लिए किराया संदेय है और इसके अन्तर्गत किराएदारी की समाप्ति के पश्चात् कब्जा चालू रखने वाला किराएदार और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इस खण्ड के क्रमशः स्पष्टीकरण-I और स्पष्टीकरण-II में विनिदिष्ट उत्तराधिकार क्रम और शर्तों के अधीन रहते

हए, उसके ऐसे उत्तराधिकारी हैं जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 में वर्णित हैं और जो उनकी मृत्यु के समय मामूली तौर से उनके साथ निवास कर रहे थे, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किराएदार द्वारा इमारत या किराए पर दी गई भूमि का अधिभोग दिया गया है, मित्राण भू-स्वामी की लिखित अनुमति के, या वह व्यक्ति जिसको सार्वजनिक मंडी, कोर्ट स्टैंड या बंधाला के किराए या फीस या दुकानों के किराए का संग्रहण ठेके पर या पट्टे पर नगरपालिका, नगर समिति या नगर या अधिमूर्चित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड द्वारा दिया गया है।

स्पष्टीकरण—I.—किराएदारी की समाप्ति के पश्चात् कब्जा चालू रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, उत्तराधिकार का क्रम निम्नलिखित होगा:—

- (क) प्रथमतः, उसकी जीवित पत्नी;
- (ख) द्वितीय, उसका पुत्र या पुत्री, या दोनों, यदि जीवित पत्नी नहीं है, या यदि जीवित पत्नी मामूली तौर पर मृतक व्यक्ति के कुटुम्ब के सदस्य के रूप में उसकी मृत्यु की तारीख तक मृतक के साथ न रही हो;
- (ग) तृतीय, उसके माता-पिता, यदि मृतक की जीवित पत्नी, पुत्र, या पुत्री नहीं है, या यदि ऐसी जीवित पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री या उनमें से कोई मृतक व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक परिमर में मृतक के कुटुम्ब के सदस्य के रूप में मामूली तौर पर न रहा हो; और
- (घ) चतुर्थ, उसकी पुत्र-वधू, उसके पूर्व मृतक पुत्र की विधवा होने के कारण, यदि मृतक व्यक्ति की जीवित पत्नी, पुत्र या पुत्री, या माता-पिता नहीं है या यदि ऐसी जीवित पत्नी, पुत्र, पुत्री या माता-पिता, या उनमें से कोई, मृतक व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक परिमर में मृतक के कुटुम्ब के सदस्य के रूप में मामूली तौर पर न रहे हों।

स्पष्टीकरण—II.—स्पष्टीकरण-I में निर्दिष्ट प्रत्येक उत्तराधिकारी का, किराएदारी की समाप्ति के पश्चात् कब्जा चालू रखने का अधिकार, उसका व्यक्तिगत होगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, उसके किसी भी उत्तराधिकारी को न्यायत नहीं होगा; और

- (च) “नगरीय क्षेत्र” से नगरपालिका, नगर समिति, छावनी बोर्ड, या अधिमूर्चित क्षेत्र समिति द्वारा शासित कोई क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

3. (1) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध किसी विशेष इमारत या किराए पर दी गई भूमि, या इमारतों या किराए पर दी गई भूमि के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे। छूट।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, सरकार के स्वामित्व में किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि को लागू नहीं होंगे।

4. (1) नियंत्रक, इमारत या किराए पर दी गई भूमि के किराएदार या भू-स्वामी के आवेदन पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि के लिए उचित किराया नियत कर सकेगा। उचित किराए का अवधारण।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उचित किराया निम्नलिखित होगा,—

- (क) उस इमारत के संबंध में जिसका निर्माण जनवरी, 1971 के पच्चीसवें दिन को या उससे पूर्व पूरा किया गया था या उक्त तारीख से पूर्व किराए पर दी गई भूमि के संबंध में, उस परिक्षेत्र में उसी प्रकार की इमारत या किराए पर दी गई भूमि के लिए जो नए किराएदार को वर्ष 1971 के दौरान किराए पर दी गई है, विद्यमान किराया; और
- (ख) उस इमारत के संबंध में, जिसका निर्माण जनवरी, 1971 के पच्चीसवें दिन के पश्चात् पूरा किया है या उक्त तारीख के पश्चात् किराए पर दी गई भूमि के संबंध में, आवेदन से पूर्ववर्ती तारीख को, भू-स्वामी और किराएदार के बीच करार पाया गया किराया, या जहां किराया करार नहीं पाया गया है वहां परिक्षेत्र में उसी प्रकार की इमारत या किराए पर दी गई भूमि के लिए आवेदन की तारीख को विद्यमान किराए के आधार पर किराया अवधारित किया जाएगा।

(3) इस बात के होते हुए भी कि इमारत या किराए पर दी गई भूमि का उचित किराया, दि ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट, 1949 या हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम, 1971 के अधीन नियत किया गया है, ऐसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि का भू-स्वामी या किराएदार इस धारा के अधीन इसका किराया [नियत कराने का हकदार होगा।

1949 का 3
1971 का 23

(4) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नियन्त्रक, कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर किराया नियत कर सकेगा और ऐसा किराया केवल पक्षकारों और उनके उत्तराधिकारियों पर ही आबद्ध कर होगा।

(5) इस धारा के अधीन नियत किया गया उचित किराया, उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस धारा के अधीन आवेदन दाखिल किया गया है।

कतिपय
दशाओं में
उचित
किराए का
पुनरीक्षण।

5. (1) उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, जब इमारत या किराए पर दी गई भूमि का किराया धारा 4 के अधीन नियत किया गया हो, तो ऐसे उचित किराए में पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई वृद्धि या कमी अनुज्ञेय नहीं होगी :

परन्तु ऐसी दशाओं में जहां वास-सुविधाओं या सुख-सुविधाओं की व्यवस्था में कमी हो गई हो, कमी अनुज्ञात की जा सकेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या संविदा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, भू-स्वामी, इस अधिनियम में उपबन्धित किराए की वृद्धि के अतिरिक्त, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् इमारत या भूमि के, यथास्थिति, उचित किराए या करार पाए गए किराए में, दस प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का हकदार होगा और ऐसी वृद्धि निम्नलिखित होगी,—

(क) ऐसी दशा में जहां ऐसी इमारत या भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष या अधिक अवधि के लिए किराए पर दी गई है—

- (i) प्रथमतः, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से, और
(ii) पुनः, ऐसे प्रारम्भ से प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से, और

(ख) जहां ऐसी इमारत या भूमि ऐसे प्रारम्भ से पूर्व पांच वर्ष से लघुतर अवधि के लिए किराए पर दी गई है और ऐसी इमारत या भूमि की ऐसी किराएदारी

के प्रारम्भ की तारीख से किराए पर रखने की अधिकतम अवधि का विस्तार पांच वर्ष से अधिक है—

(i) प्रथमतः, ऐसी किराएदारी के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति की तारीख से;

(ii) पुनः खण्ड (i) के अधीन पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख से।

(3) इस धारा के अधीन किराए की किसी वृद्धि या कमी के बारे में, भू-स्वामी और किराएदार के बीच कोई विवाद, नियंत्रक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

6. धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, जब इमारत या किराए पर दी गई भूमि का उचित किराया धारा 4 के अधीन नियत किया गया है, ऐसे उचित किराए में आगे वृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी, सिवाय उन दशाओं के जहाँ इमारत या किराए पर दी गई भूमि में कोई परिवर्धन, सुधार या परिवर्तन भू-स्वामी के खर्च पर और यदि इमारत या किराए पर दी गई भूमि तब किरायेदार के अधिभोग में है, तो उसके निवेदन पर किया गया है।

किन दशाओं में उचित किराए में वृद्धि अनुज्ञेय है।

परन्तु इस धारा के अधीन उचित किराए में वृद्धि उसी परिक्षेत्र में ऐसे ही परिवर्धन, सुधार या परिवर्तन के साथ इसी प्रकार की इमारत या किराए पर दी गई भूमि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय उचित किराए से अधिक नहीं होगी और यत्र तब तक प्रभाय नहीं होगी जब तक ऐसा परिवर्धन, सुधार या परिवर्तन पूरा नहीं हो जाता।

7. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, जब नियंत्रक द्वारा इमारत या किराए पर दी गई भूमि का उचित किराया धारा 4 के अधीन नियत किया गया है, तो—

(क) भू-स्वामी, उचित किराए के अतिरिक्त या ऐसे उचित किराए से अधिक किसी किराए का दावा नहीं करेगा या कोई प्रीमियम या उसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं करेगा किन्तु भू-स्वामी एक महीने के किराए से अधिक राशि के लिए अनुबंध कर सकेगा और उसे अधिम के रूप में प्राप्त कर सकेगा;

(ख) किराए के अतिरिक्त या ऐसे उचित किराए से अधिक किराए की किसी राशि के संदाय के लिए कोई करार भ्रूत और शून्य होगा।

भू-स्वामी द्वारा उचित किराए से अधिक किसी बात का दावा न किया जाना।

8. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू-स्वामी, किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी, उचित किराए से अधिक किसी किराए का दावा नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा।

(2) भू-स्वामी, किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि की किराएदारी या उप-किराएदारी की मन्जूरी, नवीकरण या चालू रखने के प्रतिफल स्वरूप, किराए के अतिरिक्त किसी प्रीमियम, पगड़ी, जुमाने, अधिम या इसी प्रकार की अन्य राशि का दावा नहीं करेगा या संदाय प्राप्त नहीं करेगा।

किराएदारी की मंजूरी, नवीकरण या चालू रखने के लिए जुमाने या प्रीमियम का प्रभारित न किया जाना।

9. जहाँ कोई राशि संदत्त की जा चुकी है जो राशि इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण संदेय नहीं है, ऐसी राशि, संदाय की तारीख से एक वर्ष के भीतर, या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संदाय की दशा में नियत दिन से एक वर्ष के भीतर किराएदार द्वारा जिसने यह संदत्त की थी या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा, भू-स्वामी से जिसने संदाय प्राप्त किया है या उसके विधिक

किराया जो संदत्त नहीं किया जाना था, वसूल किया जा सकेगा।

प्रतिनिधि से, किसी भी समय वसूली होगी और वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किराएदार द्वारा ऐसे एक वर्ष के भीतर ऐसे भू-स्वामी को संदेय किसी किराए में से कटौती की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में "विधिक प्रतिनिधि" अभिभ्यक्ति का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में इसका है और संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति की दशा में, संयुक्त 1908 का कटम्ब ज़िमका कि मृतक सदस्य था, इस के अन्तर्गत है।

स्थानीय प्राधिकरण के रेटों आदि के संदाय के कारण किराए की वृद्धि किन्तु अन्य कारों आदि के संदाय के कारण किराए की वृद्धि का न किया जाना।

10. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, भू-स्वामी इमारत या किराए पर दी गई भूमि के किराए में वृद्धि करने का हकदार होगा, यदि किराएदारी के प्रारम्भ के पश्चात् सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इमारत या किराए पर दी गई भूमि की बाबत कोई नया रेट, उपकर या कर उद्गृहीत किया जाता है या किराएदारी के प्रारम्भ पर उद्गृहीत ऐसे रेट, उपकर या कर की रकम में वृद्धि होती है :

परन्तु किराए में वृद्धि, यथा स्थिति, ऐसे रेट, उपकर या कर की रकम से या ऐसे रेट, उपकर या कर में वृद्धि की रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, भू-स्वामी, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, अपने किराएदार से किसी कर की रकम या उसका कोई भाग, उसके अधिभोग में किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि के सम्बन्ध में संदेय किराए की रकम में किसी वृद्धि द्वारा या अन्यथा वसूल नहीं करेगा।

आवश्यक प्रदाय या सेवा का काटना या रोकना।

11. (1) भू-स्वामी स्वयं या उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्यित किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किराएदार द्वारा, उसे किराए पर दी गई इमारत या किराए पर दी गई भूमि की बाबत उपभोग किए गए आवश्यक प्रदाय या सेवा को उचित और पर्याप्त हेतु के बिना, नहीं काटेगा अथवा रोकेंगा।

(2) यदि भू-स्वामी उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो किराएदार ऐसे उल्लंघन का परिवाद करते हुए नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा।

(3) यदि नियंत्रक का नसाधान हो जाता है कि, भू-स्वामी द्वारा आवश्यक प्रदाय या सेवा, किराएदार को परिसर खाली करने या बढ़ाया हुआ किराया संदत्त करने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से, काटी गई थी या रोकी गई थी, तो नियंत्रक, उप-धारा (4) में निर्दिष्ट जांच के लम्बित रहते हुए, भू-स्वामी को सुख-सुविधाएँ तुरन्त प्रत्यावर्तित करने का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के अधीन भू-स्वामी को नोटिस दिए बिना अन्तरिम आदेश पारित किया जा सकेगा।

(4) यदि नियंत्रक जांच करने पर यह समझता है कि इमारत या किराए पर दी गई भूमि के संबंध में किराएदार द्वारा उपयोग किया गया आवश्यक प्रदाय या सेवा, भू-स्वामी द्वारा न्यायसंगत और पर्याप्त हेतु के बिना काटी गई या रोकी गई थी, तो वह, भू-स्वामी को ऐसे प्रदाय या सेवा को प्रत्यावर्तित करने का निदेश देते हुए आदेश देगा।

(5) नियंत्रक स्वविवेकानुसार निदेश कर सकेगा कि एक सौ रूपए से अनधिक प्रतिकर,—

(क) किराएदार द्वारा, भू-स्वामी को संदत्त किया जाए, यदि उप-धारा (2) के अधीन आवेदन चुल्लतया या तंग करने की दृष्टि से किया गया था,

(ख) भू-स्वामी द्वारा किराएदार को संदत्त किया जाए, यदि भू-स्वामी ने प्रदाय या सेवा न्याय्यगत और पर्याप्त हेतु के बिना काटी या रोकी थी।

स्पष्टीकरण-I.—इस धारा में “आवश्यक प्रदाय या सेवा” के अन्तर्गत जल, विद्युत, रास्तों में, और मीठियों पर प्रकाश, सफाई और स्वच्छता सेवाओं का प्रदाय है।

स्पष्टीकरण-II.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी आवश्यक आपूर्ति या सेवा रोकने के अन्तर्गत, भू-स्वामी के वे कार्य या लोप होंगे जिनके कारण स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक प्रदाय या सेवा काटी जाती है।

12. कोई भी व्यक्ति, नियन्त्रक की लिखित अनुज्ञा के सिवाए, निवासीय इमारत को अनिवासीय इमारत में संपरिवर्तित नहीं करेगा।

निवासीय
इमारत का
अनिवासीय
इमारत में
संपरिवर्तन।

13. (1) प्रत्येक भू-स्वामी इमारत या किराए पर दी गई भूमि को अच्छी और किराए पर देन योग्य अवस्था में रखने को आबद्ध होगा।

(2) यदि भू-स्वामी, लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, युक्तियुक्त समय के भीतर कोई मरम्मत करने की, जिसके करने के लिए वह उप-धारा (1) के अधीन आबद्ध है, उपेक्षा करता है या असफल रहता है, तो किराएदार उसे स्वयं कर सकेगा और ऐसी मरम्मत के खर्च की किराए से कटौती कर सकेगा या अन्यथा भू-स्वामी से वसूल कर सकेगा।

भू-स्वामी
का इमारत
या किराए
पर दी गई
भूमि को
अच्छी
अवस्था में
रखने का
कर्तव्य।

परन्तु किसी वर्ष में इस प्रकार कटौती की गई या वसूलीय रकम, किराएदार द्वारा उम वर्ष के लिए संदेय किराए के बाग़हूँ भाग से अधिक नहीं होगी।

(3) जहाँ ऐसी मरम्मत की जाती है जिसके बिना इमारत या किराए पर दी गई भूमि, सिवाए असम्यक् असुविधा के दीर्घतर वासयोग्य या उपयोग किए जाने योग्य नहीं है, और भू-स्वामी लिखित नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उसे करने की उपेक्षा करता है या असफल रहता है, तो किराएदार ऐसी मरम्मत स्वयं करवाने की अनुज्ञा के लिए नियंत्रक को, आवेदन कर सकेगा और ऐसी मरम्मत की लागत का प्राक्कलन नियंत्रक को प्रस्तुत कर सकेगा, और तदुपरि, नियंत्रक भू-स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लागत के ऐसे प्राक्कलन पर विचार करने और ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, किराएदार को ऐसी मरम्मत, ऐसी लागत पर करने की जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञा दे सकेगा और तत्पश्चात् किराएदार के लिए, ऐसी मरम्मत स्वयं करवाना और उसकी लागत की, जो किसी भी दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी, किराए से कटौती करना या अन्यथा भू-स्वामी से वसूल करना, विधिपूर्ण होगा।

परन्तु किसी भी वर्ष में इस प्रकार कटौती की गई या वसूलीय रकम, किराएदार द्वारा संदेय तीन मास के किराए से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि कोई मरम्मत जो उक्त रकम द्वारा पूरी नहीं होती है, नियंत्रक की राय में आवश्यक है और किराएदार अतिरिक्त लागत का भार स्वयं उठाने के लिए सहमत हो जाता है, तो नियंत्रक किराएदार को ऐसी मरम्मत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

किराएदारों की बेदखली। 14. (1) इमारत या किराए पर दी गई भूमि पर कब्जा रखने वाले किराएदार को वहां से, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् पारित डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा और चाहे किराएदारी के पर्यवसान से पूर्व या पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार के सिवाए, बेदखल नहीं किया जाएगा।

(2) भू-स्वामी जो अपने किराएदार को बेदखल करना चाहता है, नियंत्रक को उस निमित्त निदेश देने के लिए आवेदन करेगा। यदि नियंत्रक का, किराएदार को आवेदक के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि—

- (i) किराएदार ने, अपने भू-स्वामी के साथ किराएदारी के करार में नियत समय के अवसान के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे किसी करार के अभाव में, ठीक आगामी मास के, जिसके लिए किराया संदेय है, अन्तिम दिन तक, इमारत या किराए पर दी गई भूमि के संबंध में उस द्वारा संदेय किराया संदत्त या निविदत्त नहीं किया है :

परन्तु यदि किराएदार, सम्यक् तामील के पश्चात् बेदखली के आवेदन की प्रथम सुनवाई पर, किराए की बकाया और ऐसी बकाया पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, नियंत्रक द्वारा निर्धारित आवेदन की लागत सहित संदत्त या निविदत्त करता है, तो यह समझा जाएगा कि किराएदार ने किराया पूर्वोक्त समय के भीतर सम्यक् रूप से संदत्त या निविदत्त कर दिया है :

परन्तु यह और कि यदि बकाया, नियत दिन से पूर्वतर अवधि का है, तो ब्याज छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि वह किराएदार जिसके विरुद्ध उस द्वारा देय किराए के असंदाय के आधार पर, नियंत्रक ने बेदखली का आदेश दिया है, उसके आदेश के परिणामस्वरूप बेदखल नहीं किया जाएगा, यदि किराएदार, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर देय रकम संदत्त कर देता है; या

- (ii) किराएदार ने, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् भू-स्वामी की लिखित अनुमति के बिना—

- (क) पट्टे के अधीन अपने अधिकार अन्तर्गत किए हैं या सम्पूर्ण इमारत या किराए पर दी गई भूमि या उसका कोई भाग शिकमी पट्टे पर दिया है; या

- (ख) इमारत या किराए पर दी गई भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया है जिस के लिए यह पट्टे पर दी गई थी;

- (iii) किराएदार ने ऐसे कार्य किए हैं जिनसे इमारत या किराए पर दी गई भूमि के मूल्य या उसकी उपयोगिता में तात्त्विक ह्रास संभाव्य है;

- (iv) किराएदार ऐसे कार्यों और आचरण का दोषी रहा है जो पड़ोस की इमारतों के अधिभोगियों के लिए उपताप (न्यूसैंस) हैं;

- (v) किराएदार का, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, बारह मास की लगातार अवधि के लिए इमारत या किराए पर दी गई भूमि का अधिभोग नहीं रहा है;

तो नियंत्रक किराएदार को, इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा भू-स्वामी को देने के लिए, निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा और यदि नियंत्रक का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश देगा :

परन्तु नियंत्रक, किराएदार को इमारत या किराए पर दी गई भूमि का भू-स्वामी को कब्जा देने के लिए, युक्तियुक्त समय दे सकेगा और ऐसा समय भी बढ़ा सकेगा जिस से कि वह कुल मिला कर तीन मास से अधिक न हो ।

(3) भू-स्वामी को कब्जा देने के लिए, किराएदार को निदेश करने वाले आदेश के लिए भू-स्वामी, नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा,—

(क) निवासीय इमारत की दशा में, यदि—

(i) यह उसे स्वयं अपने अधिभोग के लिए अपेक्षित है :

परन्तु यह तब जब कि वह सम्बद्ध नगरीय क्षेत्र में उसके स्वामित्व में किसी दूसरी निवासीय इमारत का, अधिभोग न कर रहा हो :

परन्तु यह और कि उसने उक्त नगरीय क्षेत्र में, ऐसी इमारत पर्याप्त हेतुक के बिना आवेदन दायर करने के पांच वर्ष के भीतर खाली नहीं की है, या

(ii) यह किराएदार को, भू-स्वामी की सेवा या नियोजन में होने के कारण, आवाम के रूप में प्रयोग के लिए किराए पर दी गई थी और किराएदार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है :

परन्तु जहां किराएदार ऐसा कर्मकार है, जिसे भू-स्वामी द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के उल्लंघन में अपनी सेवा या नियोजन से उन्मुक्त या पदच्युत किया गया है, वह तब तक वेदखल किए जाने का दावा नहीं होगा, जब तक उस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, भू-स्वामी द्वारा उसके विरुद्ध किए गए उन्मुक्ति या पदच्युति आदेश की पुष्टि नहीं करता है;

(iii) भू-स्वामी, भारत संघ के सशस्त्र बल का सदस्य है और यह उसके कुटुम्ब के अधिभोग के लिए अपेक्षित है और यदि वह भारतीय सैनिक (मुकद्मा) अधिनियम, 1925 की धारा 7 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह उस अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में सेवा कर रहा है या अकुटुम्ब स्टेशन पर पदस्थित है ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए —

- (1) विहित प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि भू-स्वामी विशेष परिस्थितियों में सेवा कर रहा है या अकुटुम्ब स्टेशन पर पदस्थित है;
- (2) "कुटुम्ब" से भू-स्वामी के माता-पिता और ऐसे नातेदार जो मामूली तौर पर उसके साथ निवास करते हैं और उस पर आश्रित हैं अभिप्रेत हैं;

1947 का 14

1925 का 4

(iv) किराएदार ने, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अपनी अपेक्षाओं के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त आवास का, निर्माण किया है या खाली का कब्जा अर्जित किया है या उसे आबंटित किया गया है;

(ख) किराए पर दी गई भूमि की दशा में, यदि —

(i) यह उसे स्वयं अपने उपयोग के लिए अपेक्षित है :

परन्तु यह तब जब कि सम्बद्ध नगरीय क्षेत्र में वह अपने कारबार के लिए किराए पर दी गई किसी दूसरी भूमि का अधिभोग नहीं कर रहा हो :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध नगरीय क्षेत्र में उसने, किराए पर दी गई ऐसी भूमि पर्याप्त हेतुक के बिना, आवेदन दायर करने के पांच वर्ष के भीतर खाली नहीं की है ;

(ii) किराए पर दी गई भूमि उस द्वारा, निवासीय या अनिवासीय इमारत के सन्निर्माण या उद्योग की स्थापना के लिए, अपेक्षित है ;

(iii) किराएदार, किराए पर दी गई अपनी भूमि को, किसी अन्य व्यक्ति को उच्चतर किराए पर देता है ;

(ग) किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि की दशा में, यदि यह उसे किसी सुधार या विकास स्कीम के अधीन सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सुधार न्यास की प्रेरणा पर, या यदि वह मानवीय वास के लिए असुरक्षित या अयोग्य हो गई है, तो किसी निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित है या वास्तव में ऐसी मरम्मत के निष्पादन के लिए उस द्वारा अपेक्षित है जो इमारत या किराए पर दी गई भूमि को खाली किए बिना निष्पादित नहीं की जा सकती है या वास्तव में इमारत या किराए पर दी गई भूमि उस द्वारा निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें कोई सारभूत परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित है और ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन इमारत या किराए पर दी गई भूमि को खाली किए बिना, निष्पादित नहीं किया जा सकता है ;

(घ) किसी निवासीय इमारत की दशा में, यदि यह उसे अपने ऐसे पुत्र के, जो वकील, वास्तुविद, दंत-चिकित्सक, अभियन्ता, पशु-चिकित्सा सर्जन या चिकित्सा व्यवसायी, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी, या होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति का व्यवसायी भी है, के रूप में व्यवसाय करने का इरादा रखता है, कार्यालय, या परामर्श कक्ष के रूप में प्रयोग के लिए या अपने विवाहित पुत्र के आवास के लिए अपेक्षित है, यदि —

(i) सम्बद्ध नगरीय क्षेत्र में, यथापूर्वोक्त उसका पुत्र, यथास्थिति, कार्यालय, परामर्शकक्ष या आवास के रूप में किसी अन्य इमारत का अधिभोग नहीं कर रहा है ; और

(ii) उसके यथापूर्वोक्त पुत्र ने, सम्बद्ध नगरीय क्षेत्र में, ऐसी इमारत को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् पर्याप्त हेतुक के बिना खाली नहीं किया है :

परन्तु जहां भू-स्वामी और किराएदार के बीच किराएदारी, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए करार पाई गई है, वहां भू-स्वामी ऐसी अवधि के अवसान

मे पूर्व इस उप-धारा के अधीन आवेदन करने के लिए, हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां भू-स्वामी ने किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन अभिप्राप्त किया है, वह उसी वर्ग की किसी अन्य इमारत या किराए पर दी गई भूमि के कब्जे के लिए उक्त खण्ड के अधीन पुनः आवेदन करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां भू-स्वामी ने किसी इमारत का कब्जा खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन अभिप्राप्त किया है, वह उसी पुत्र के, यथास्थिति, उपयोग या आवास के लिए उक्त खण्ड के अधीन पुनः आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि भू-स्वामी का दावा यथार्थ है, किराएदार को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वह ऐसी तारीख को जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा भू-स्वामी को देना और यदि नियंत्रक का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो वह आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश करेगा :

परन्तु नियंत्रक, किराएदार को, इमारत या किराए पर दी गई भूमि का भू-स्वामी को कब्जा देने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकेगा और ऐसे समय की इतनी वृद्धि कर सकेगा कि वह कुल मिला कर तीन मास से अधिक न हो ।

(5) जहां कोई भू-स्वामी, जिसने इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा उप-धारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में अभिप्राप्त किया है, स्वयं उसका अधिभोग नहीं करता है या, यदि उसके द्वारा कब्जा उसके कुटुम्ब के लिए उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) के अधीन आदेश के अनुसरण में अभिप्राप्त किया गया था, उसका कुटुम्ब आवासीय इमारत का अधिभोग नहीं करता है या यदि उसके द्वारा कब्जा उसके पुत्र की ओर से उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन आदेश के अनुसरण में अभिप्राप्त किया गया था, उसका पुत्र उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए कब्जा अभिप्राप्त किया गया था उसका अधिभोग कब्जा प्राप्त करने की तारीख से बारह मास को निरन्तर अवधि तक नहीं करता है या यदि कब्जा धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अभिप्राप्त किया गया था, वह निजी उपयोग के लिए उसका अधिभोग, कब्जा प्राप्त करने की तारीख से निरन्तर तीन मास की अवधि तक नहीं करता है, या जहां वह भू-स्वामी जिसने इमारत का कब्जा उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अभिप्राप्त किया है, उस इमारत को उससे भिन्न किसी उपयोग में लाता है जिसके लिए यह अभिप्राप्त की गई थी या उसे बेदखल किए गए किराएदार से भिन्न किसी किराएदार को किराए पर देता है, तो वह किराएदार जिसे बेदखल किया गया है, नियंत्रक को यह निदेश देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि ऐसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा उसे प्रत्यावर्तित किया जाए और नियंत्रक तदनुसार आदेश करेगा ।

(6) जहां भू-स्वामी ने कोई परिसर अन्तरण द्वारा अर्जित किया है, इस धारा के अधीन, उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट आधार पर ऐसे परिसर के कब्जे की वापसी के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हो गई हो ।

(7) जहां नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि भू-स्वामी द्वारा किराएदार की बेदखली के लिए किया गया आवेदन, तुच्छतया या तंग करने वाला है वहां नियंत्रक निदेश

दे सकेगा कि किराएदार को ऐसे व्यक्ति द्वारा, पांच सौ रुपये से अनधिक प्रतिकूल मंदत किया जाए।

कतिपय
व्यक्तियों का
परिसर का
तुरन्त कब्जा
वापस लेने
का अधि-
कार।

15. (1) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवंटित किसी निवासीय परिसर का अधिभोगी व्यक्ति होते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या के अनुसरण में, ऐसे आवासीय आवास को खाली करना, या व्यक्तिगत में कतिपय बाध्यताएं इस आधार पर उपगत करना अपेक्षित है, कि, नगरीय क्षेत्र के भीतर, उसके या उसकी पत्नी/पति या आश्रित संतान के स्वामित्व में आवासीय आवास वहां ऐसे आदेश की तारीख पर और से इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा (चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित), प्रतिकूल रूढ़ि या प्रथा में कहीं भी किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस द्वारा किराए पर दिए किसी परिसर का तुरन्त कब्जा लेने का ऐसे व्यक्ति का अधिकार, प्रोदभूत होगा:

परन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह उस व्यक्ति को जिसके अपने या उसकी पत्नी या आश्रित संतान के स्वामित्व में नगरीय क्षेत्र में, दो या अधिक निवास-गृह हों, एक से अधिक निवास गृहों का कब्जा वापस लेने का अधिकार प्रदान करती है, और ऐसे व्यक्ति के लिए उस निवास-गृह को उपदर्शित करना जिसका कब्जा वह वापस लेना चाहता है, विधिपूर्ण होगा।

(2) जहां विनिर्दिष्ट भू-स्वामी, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व या उसके पश्चात् एक वर्ष के भीतर या अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी भी समय किन्तु नियत दिन से एक वर्ष के भीतर, जो भी पश्चात्तर्वर्ती हो, नियंत्रक को, उसे सेवा से हटाने वाले सक्षम प्राधिकारी के उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उपदर्शित करते हुए प्रमाण-पत्र और इस आशय के अपने शपथ-पत्र सहित कि उस स्थानीय क्षेत्र में जहां वह निवास करने या अपना कारबार चलाए का इरादा रखता है, उसके या उसकी पत्नी के स्वामित्व और कब्जे में कोई उपयुक्त वास सुविधा नहीं है, एक आवासीय इमारत का कब्जा वापस लेने के लिए, आवेदन करता है, वहां ऐसे विनिर्दिष्ट स्वामी का, ऐसे आवेदन की तारीख को और से, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा (चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित), प्रतिकूल रूढ़ि या प्रथा में, किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसी आवासीय इमारत या ऐसी इमारत के भाग या भागों का, यदि यह भाग या भागों में, किराए पर दी गई है, तुरन्त कब्जा वापस लेने का अधिकार प्रोदभूत होगा:

परन्तु विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की मृत्यु की दशा में, ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की विधवा या विधुर और ऐसी विधवा या विधुर की मृत्यु की दशा में माता या पिता या संतान या पोता-पोती या विधवा पुत्र-वधु जो ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी पर उसकी मृत्यु के समय आश्रित थी, इस धारा के अधीन नियंत्रक को आवेदन करने के हकदार होंगे,—

(क) नियत दिन से पूर्व ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की मृत्यु की दशा में, ऐसे नियत दिन से एक वर्ष के भीतर;

(ख) नियत दिन के पश्चात् किन्तु उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व, ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की मृत्यु की दशा में, उसकी मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर;

- (ग) नियत दिन और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की मृत्यु की दशा में, ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर; और ऐसे आवेदन की तारीख को, आवासीय इमारत जो ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी या उसकी पत्नी की मृत्यु के समय उसकी थी, के कब्जे को वापस लेने का अधिकार, आवेदक को प्रोद्भूत होगा :

परन्तु यह और कि इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी व्यक्ति को एक आवासीय इमारत से इसके भाग या भागों सहित, यदि इसे भाग या भागों में किराए पर दिया गया है, अधिक का कब्जा वापस लेने का अधिकार प्रदान करती है :

परन्तु यह और भी कि नियन्त्रक, किराएदार को, विनिर्दिष्ट भू-स्वामी या, यथास्थिति, विधवा, विधुर, संतान, पोता-पोती, या विधवा पुत्र-पुत्री को, आवासीय इमारत का कब्जा देने के लिए, युक्तियुक्त समय, दे सकेगा और ऐसा समय इस प्रकार बढ़ा सकेगा कि वह कुल मिला कर तीन मास में अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छा सेवानिवृत्ति, "सेवानिवृत्ति" अभि-व्यक्ति के अन्तर्गत है किन्तु इसके अन्तर्गत सेवा में त्यागपत्र, सेवान्मक्ति या पदच्युति नहीं है।

(3) इस अधिनियम में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संवि-तत्प्रतिकूल रूढ़ि या प्रथा में कहीं भी किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां भू-स्वा-इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त वापसी के अधिकार का प्रयोग करता है, वहां उस द्वारा किराएदार को या उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, क-प्रतिकर संदेय नहीं होगा और ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां भू-स्वामी ने,—

- (क) किराएदार से कोई अधिम किराया प्राप्त किया है, वह, उस द्वारा परिसर का कब्जा वापस लेने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर किराएदार को ऐसी रकम का प्रतिदाय करेगा, जो संविदा, करार या पट्टे के अनवसित प्रभाग के लिए संदेय किराया, व्यपदिष्ट करती है;
- (ख) कोई अन्य संदाय प्राप्त किया है, वह, पूर्वोक्त अवधि के भीतर, किराएदार को ऐसी राशि का प्रतिदाय करेगा जो ऐसे प्राप्त की गई कुल रकम के उसी अनुपात की होगी जो संविदा करार या पट्टे के अनवसित प्रभाग का, संविदा या करार या पट्टे की कुल अवधि से है :

परन्तु यह और कि यदि यथापूर्वोक्त किसी प्रतिदाय को करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो भू-स्वामी नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से माधारण ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगा।

16. (1) धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) या धारा 15 के अधीन, भू-स्वामी द्वारा किसी परिसर के कब्जे को वापस लेने के लिए प्रत्येक आवेदन का, इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, निपटारा किया जाएगा।

धारा 14
(3) (क)
(iii) और

धारा 15 के अधीन वास्तविक अपेक्षा के आधार पर बेदखली के लिए आवेदन के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया। (2) धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) या धारा 15 के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, नियंत्रक, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक आवेदन के सम्बन्ध में, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्ररूप में समन जारी करेगा।

(3) (क) नियंत्रक, किराएदार पर तामील के लिए समन जारी करने के अतिरिक्त और साथ-साथ, यह निदेश भी देगा कि समन की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, किराएदार या समन स्वीकार करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को, उस स्थान पर की जाए जहां किराएदार या उसका अभिकर्ता वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार चलाता है या व्यक्तिगत रूप में फायदे के लिए कार्य करता है, और यदि मामले की परिस्थितियों द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, किराएदार के अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार या फायदे के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले परिक्षेत्र में परिचालित समाचार पत्र में समन के प्रकाशन का निदेश भी दे सकेगा।

(ख) जब किराएदार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होनी तात्पर्यित अभिस्वीकृति, नियंत्रक द्वारा प्राप्त की जाती है, या समन युक्त रजिस्ट्री डाक विभाग के कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले तात्पर्यित इस पृष्ठांकन के साथ वापस आ जाती है कि किराएदार या उसके अभिकर्ता ने रजिस्ट्री प्राप्त करने से इन्कार कर दिया है तब यदि नियंत्रक का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, पृष्ठांकन के सही होने के बारे में समाधान हो जाता है, वह घोषणा कर सकेगा कि किराएदार पर समन की विधिमान्य तामील हो गई है।

(4) वह किराएदार जिसको अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्ररूप में समन की सम्यक् रूप से तामील की गई है (चाहे साधारण तरीके से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा) परिसर से बेदखली के लिए प्रार्थना पर प्रतिवाद नहीं करेगा, जब तक कि वह उन आधारों का कथन करते हुए शपथ-पत्र दाखिल नहीं करता है, जिन पर वह बेदखली के आवेदन पर प्रतिवाद करना चाहता है और नियंत्रक से इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित अनुमति अभिप्राप्त नहीं करता है; और समन के अनुसरण में उसकी उपस्थिति या उसके ऐसी अनुमति अभिप्राप्त करने के व्यतिक्रम में, भू-स्वामी द्वारा या विनिर्दिष्ट भू-स्वामी द्वारा, या यथा-स्थिति, ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की विधवा, विधुर, सन्तान, पोता-पोती या विधवा पुत्र-वधु द्वारा बेदखली के आवेदन में किए कथन को किराएदार द्वारा स्वीकृत किया गया समझा जाएगा और आवेदक पूर्वोक्त आधार पर बेदखली के लिए आदेश का हकदार होगा।

(5) नियंत्रक, किराएदार को आवेदन का प्रतिवाद करने की अनुमति देगा यदि किराएदार द्वारा दाखिल किया गया शपथ-पत्र ऐसा तथ्य प्रकट करता है जो भू-स्वामी या विनिर्दिष्ट भू-स्वामी या, यथास्थिति, ऐसे विनिर्दिष्ट भू-स्वामी की विधवा, विधुर, सन्तान, पोता-पोती या विधवा पुत्र-वधु को, धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) या धारा 15 में विनिर्दिष्ट आधार पर परिसर का कब्जा वापस लेने के लिए आदेश अभिप्राप्त करने के, हक से वंचित करता है।

(6) जहां किराएदार को आवेदन का प्रतिवाद करने की अनुमति मंजूर की जाती है, वहां नियंत्रक, आवेदन की मुनवाई, यथासाध्य शीघ्रता से प्रारम्भ करेगा।

(7) धारा 14 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी नियंत्रक, कार्यवाही में जांच करते समय लघु वाद न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का, साक्ष्य अभिलिखित करने सहित, अनुसरण करेगा।

(8) इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक द्वारा परिसर के कब्जे की वापसी के लिए किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील या दूसरी अपील नहीं होगी।

परन्तु उच्च न्यायालय, अपने समाधान के प्रयोजन के लिए कि नियंत्रक द्वारा इस धारा के अधीन किया गया आदेश विधि के अनुसार है, मामले के अभिलेखों को मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे यह उचित समझे।

(9) जहाँ उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, नियंत्रक, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश XLVII के उपबंधों के अनुसार, पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। 1908 का 5

(10) इस धारा में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) और धारा 15 में विनिर्दिष्ट आधार पर वेदखली के लिए आवेदन को निपटाने की प्रक्रिया वही होगी जो नियंत्रक द्वारा आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया है।

17. जहाँ भू-स्वामी द्वारा, विशिष्ट कालावधि के लिए कोई परिसर सम्पूर्ण या उसका कोई भाग अपेक्षित नहीं है, और भू-स्वामी, विहित रीति में नियंत्रक की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, सम्पूर्ण परिसर या उसका कोई भाग निवाम के रूप में, ऐसी अवधि के लिए जो लिखित रूप में भू-स्वामी और किराएदार के बीच करार पाई जाए, किराए पर देता है, और किराएदार कथित अवधि के अवसान पर ऐसे परिसर को खाली नहीं करता है, तब धारा 14 या किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नियंत्रक, भू-स्वामी द्वारा इस संबंध में, ऐसे समय में जो विहित किया जाए, उसे किए गए किसी आवेदन पर, भू-स्वामी को परिसर या उसके भाग का, किराएदार और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को जो भी ऐसे परिसर के अधिभोग में हों, बेदखल करके, खाली का कब्जा दे सकेगा।

परिसीमित अवधि की किराएदारी की दशा में कब्जे की वापसी।

18. नियंत्रक, धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन किसी आवेदन को, जो सारतः ऐसे विवाद्यक उठाता है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी पूर्ववर्ती कार्यवाही में अंतिम रूप में विनिश्चित कर दिए गए हैं, संक्षेपतः नामंजूर कर देगा।

जो विनिश्चय अन्तिम हो चुके हैं उन को पुनः चालू न करना।

19. जब कभी भी कोई इमारत, जिसका सन्निर्माण इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया गया था और किराएदारों को किराए पर दी जाती रही थी, बारह मास की अवधि के लिए खाली रहती है, नियंत्रक, किसी व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर, भू-स्वामी को यह संसूचित करते हुए नोटिस दे सकेगा कि उसे कारण बताना होगा कि खाली इमारत को क्यों किराएदार को किराए पर न दिया जाए, जो भू-स्वामी को उचित किराया संदत्त करेगा। नियंत्रक, भू-स्वामी की सुनवाई पर, ऐसे निबन्धनों पर जिन पर इमारत किराए पर दी जा रही थी, उसे ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगा जिसके अधिभोग में स्वामी या किराएदार के रूप में कोई अन्य इमारत नहीं है।

खाली इमारतों का पट्टे पर देना।

20. (1) प्रत्येक किराएदार, संविदा द्वारा नियत समय के भीतर, या ऐसी संविदा के अभाव में, उस मास से ठीक आगामी मास के पंद्रहवें दिन तक, जिसके लिए यह संदेय है, किराए का संदाय करेगा। संदत्त किराए के लिए रसीद देना।

(2) प्रत्येक किराएदार जो अपने भू-स्वामी को किराया संदत्त करता है, अपने भू-स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से, उसको संदत्त रकम के लिए तत्काल भू-स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित रसीद अभिप्राप्त करने का, हफ्तवार होगा।

(3) यदि भू-स्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता, किराएदार को उप-धारा (2) में निर्दिष्ट रसीद देने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है, तो नियंत्रक, किराएदार द्वारा इस निमित्त संदाय की तारीख से दो मास के भीतर उसको दिए गए आवेदन पर और भू-स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के पश्चात् आदेश द्वारा भू-स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को, किराएदार द्वारा संदत्त किराए की राशि के दुगुने से अनधिक राशि और आवेदन की लागत किराएदार को नुकसानी के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा और संदत्त किराए के बारे में किराएदार को प्रमाण-पत्र भी देगा।

किराएदार द्वारा किराया जमा करवाना। 21. (1) जहाँ भू-स्वामी धारा 20 में निर्दिष्ट समय के भीतर किराएदार द्वारा निविदत्त किसी किराए को स्वीकार नहीं करता है या उसमें निर्दिष्ट रसीद देने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है या जहाँ उस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जिन्हें किराया संदेय है, यथार्थ संदेह है, वहाँ किराएदार विहित रीति में नियंत्रक के पास ऐसा किराया जमा करवा सकेगा।

(2) जमा से निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त किराएदार का आवेदन संलग्न होगा, अर्थात्:—

- (क) इमारत या किराए पर दी गई भूमि जिसके लिए किराया जमा किया गया, इमारत या किराए पर दी गई भूमि, की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण सहित ;
- (ख) वह अवधि जिसके लिए किराया जमा कराया गया ;
- (ग) भू-स्वामी या ऐसे किराए का हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते ; और
- (घ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं।

(3) किराए के ऐसे जमा करवाने पर नियंत्रक, भू-स्वामी या किराए का हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को, विहित रीति में आवेदन की प्रति या प्रतियाँ जमा करवाने की तारीख के पृष्ठांकन के साथ भेजेगा।

(4) यदि किराए की किसी जमा राशि के निकालने के लिए आवेदन किया जाता है, तो नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक जमा किए गए किराए को प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति है, तो किराए की जमा रकम को उसे विहित रीति में संदत्त करने का आदेश देगा :

परन्तु नियंत्रक द्वारा किराए की किसी जमा राशि के संदाय के लिए इस उप-धारा के अधीन आदेश किराएदार द्वारा उप-धारा (2) के अधीन अपने आवेदन में ऐसे किराए के संदाय के लिए हकदार होने का दावा करने वाले नामित सभी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, नहीं दिया जायेगा और ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने पर ऐसे व्यक्तियों के ऐसे किराए को प्राप्त करने के अधिकारों पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(5) यदि उप-धारा (4) के अधीन आवेदन दाखिल करने के समय किन्तु जमा का नोटिस प्राप्त करने के तीस दिनों के अवसान के पश्चात् नहीं, भू-स्वामी या किराए के लिए हकदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति या व्यक्तिगण, नियंत्रक को परिवाद करते हैं कि किराएदार के आवेदन में कारणों और परिस्थितियों का कथन जिनके कारण उसे किराया जमा करवाना पड़ा, असत्य है, तो नियंत्रक, किराएदार को सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात्, किराएदार पर ज़माना उद्गृहीत कर सकेगा जो दो महीने के किराए की रकम के बराबर हो सकेगा, यदि नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि कथित कथन तात्त्विक रूप से असत्य थे, और आदेश कर सकेगा कि वसूल किए गए ज़माने में से भू-स्वामी को प्रतिकर के रूप में राशि संदत्त की जाए।

(6) नियंत्रक, किराएदार के परिवाद पर और भू-स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, भू-स्वामी पर ज़माना उद्गृहीत कर सकेगा जो दो मास के किराए की रकम के बराबर हो सकेगा, यदि नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि भू-स्वामी ने, किसी व्यक्तिगत त्रेनुक के बिना, किराया स्वीकार करने से इन्कार किया है यद्यपि यह उसे धारा 20 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निविदत्त किया गया था, और आगे आदेश कर सकेगा कि वसूल किए गए ज़माने में से किराएदार को प्रतिकर के रूप में राशि संदत्त की जाए।

22. (1) धारा 21 के अधीन जमा किया गया किराया उस धारा के अधीन विधि-पूर्वक जमा किया गया नहीं माना जायेगा, जब तक कि जमा, धारा 20 में निर्दिष्ट किराए के संदाय के लिए निर्दिष्ट समय से इक्कीस दिन के भीतर न किया गया हो।

जमा करवाने के लिए समय की परिसीमा और जमा के लिए आवेदन में गलत विशिष्टियों के परिणाम।

(2) ऐसा जमा विधिमान्यता किया गया नहीं माना जायेगा यदि किराएदार किराया जमा करने के अपने आवेदन में जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन करता है, जब तक कि भू-स्वामी ने इमारत या किराए पर दी गई भूमि का कब्जा वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से पूर्व जमा रकम न निकाली हो।

(3) यदि किराया उप-धारा (1) में वर्णित समय के भीतर जमा किया जाता है और उप-धारा (2) में वर्णित कारण से इसका विधिमान्य जमा होना समाप्त नहीं होता है, तो जमा, भू-स्वामी को किराए का संदाय होगा, मानो कि जमा रकम विधिमान्यतः निविदत्त की गई है।

23. (1) धारा 21 के अधीन जमा किराए का उसमें उपबन्धित रीति से निकाला जाना इसे निकालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किराए की दर, व्यतिक्रम की अवधि, देय रकम, या किराएदार के आवेदन में उक्त धारा के अधीन किराया जमा कराने के लिए विवर्णित किन्हीं, अन्य तथ्यों के सही होने की स्वीकृति के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा।

किराए की स्वीकृति और जमा किराए के समपहरण की व्यावृत्तियां।

(2) कोई जमा किराया जो भू-स्वामी या ऐसा किराया प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निकाला नहीं जाता है तो नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश द्वारा सरकार को समपहृत किया जायेगा, यदि यह जमा करने के नोटिस के डाक द्वारा भेजने की तारीख से पांच वर्ष के अवसान से पूर्व नहीं निकाला जाता।

(3) समपहरण का आदेश पारित करने से पूर्व नियंत्रक, भू-स्वामी या जमा किराए को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को, नोटिस ऐसे भू-स्वामी या व्यक्ति या व्यक्तियों के अन्तिम ज्ञात पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा और नोटिस को अपने कार्यालय में और किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करेगा।

राज्य सरकार द्वारा अपील प्रधिकार का अधिकाधिकारियों में निहित किया जाना ।

24. (1) (क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश से अधिसूचना द्वारा, ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे क्षेत्र में या मामलों के ऐसे वर्गों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपील प्राधिकारियों की शक्तियां प्रदान कर सकेगी ।

(ख) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सिवाय नियंत्रक द्वारा धारा 16 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार कब्जे की वापसी के लिए किए गए आदेश के, ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जो अपील प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञात करे, अधिकारिता प्राप्त अपील प्राधिकारी को, लिखित अपील कर सकेगा (पंद्रह दिन की अवधि की गणना में, उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे समय को अपवर्जित किया जायेगा) ।

(2) ऐसी अपील किए जाने पर, अपील प्राधिकारी अपील पर विनिश्चय लम्बित रहने तक मामले में अगली कार्यवाहियों को रोकने का आदेश कर सकेगा ।

(3) अपील प्राधिकारी, नियंत्रक से मामले के अभिलेख मंगवाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और, यदि आवश्यक हो, व्यक्तिगत रूप से या नियंत्रक के माध्यम से, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो यह उचित समझे, अपील विनिश्चित करेगा ।

(4) अपील प्राधिकारी का विनिश्चय और केवल ऐसे विनिश्चय के अधीन रहते हुए नियंत्रक का आदेश, अंतिम होगा और इस धारा की उप-धारा (5) में यथा उपबन्धित के सिवाय, पालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

(5) उ । किसी भी समय, किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से न के अधीन पारित किसी आदेश या की गई कार्यवाही से संबद्ध अभिलेखों का एक आदेश या कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन में मंगा सकेगा और परीक्षण कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

साक्षियों को समन करने और उपस्थित कराने की शक्ति ।

25. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी या नियंत्रक को साक्षियों को समन करने और उपस्थित कराने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित हैं ।

1908 का 5

आवेदनों का निष्पादन ।

26. धारा 31 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा किया गया कोई आदेश या अपील पर पारित कोई आदेश, नियंत्रक द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए, नियंत्रक को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

आवेदनों का संस्थित करना और निष्पान्त ।

27. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, एक ही राज्य क्षेत्र में दो या अधिक नियंत्रक एक ही स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं, वहां ऐसे नियंत्रकों में से जो ज्येष्ठतम (सेवा में) है, केवल वही इस अधिनियम के अधीन आवेदनों और कार्यवाहियों को प्रारम्भिक तौर पर ग्रहण करने के लिए सक्षम होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन, उप-धारा (1) के अधीन, आवेदनों और कार्यवाहियों को ग्रहण करने के लिए सक्षम नियंत्रक, उसके समक्ष लंबित ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों या आवेदनों को, किसी अन्य सक्षम अधिकारिता प्राप्त नियंत्रक को निपटाने के लिए अन्तरित कर सकेगा।

28. (1) उच्च न्यायालय, इसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा आदेश द्वारा, किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही को, अन्य अपील प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा और वह अपील प्राधिकारी जिसको कार्यवाही अन्तरित की जाती है, अन्तरण आदेश में किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, कार्यवाहियों का निपटान कर सकेगा।

कार्यवाहियों को अन्तरित करने की शक्ति।

(2) उच्च न्यायालय या अपील प्राधिकारी, इसे आवेदन किए जाने पर या अन्यथा आदेश द्वारा, किसी नियंत्रक के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को, अपनी अधिकारिता के भीतर अन्य किसी नियंत्रक को अन्तरित कर सकेगा और नियंत्रक जिसको कार्यवाही अन्तरित की जाती है, अन्तरण आदेश में किसी विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, कार्यवाहियों को निपटा सकेगा।

29. किसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि का प्रत्येक भू-स्वामी और प्रत्येक किराएदार, नियंत्रक को या उस द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, ऐसी इमारत या किराए पर दी गई भूमि के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ, जो विहित की जाएँ, देने के लिए आबद्ध होगा।

भू-स्वामी और किराएदार द्वारा विशिष्टियों का दिया जाना।

30. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 29 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

शस्तियाँ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 के खण्ड (क) या धारा 8 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(3) विनिर्दिष्ट भू-स्वामी या ऐसे भू-स्वामी की, यथास्थिति, विधवा, विधुर, माता-पिता, सन्तान, पोता-पोती या विधवा पुत्र-वधु, जो धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किराएदार को इमारत से बेदखल करने पर ऐसी बेदखली की तारीख से तीन मास की निरंतर अवधि के लिए इसका अधिभाग नहीं लेता है; या ऐसी सम्पूर्ण इमारत या उसके किसी भाग को, जिसमें से किराएदार को बेदखल किया गया था, किराएदार से अन्य किसी व्यक्ति को किराए पर देता है, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(5) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा, जब तक कि अपराध के संबंध में परिवाद अपराध के किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर न किया गया हो।

जुर्माने की वसूली के लिए नियंत्रक, मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करेगा। 31. इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना, उस व्यक्ति द्वारा जिसे जुर्माना किया गया है, ऐसे समय के भीतर संदत्त किया जाएगा जो नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात किया जाए और नियंत्रक ठोस और पर्याप्त कारण से समय बढ़ा सकेगा, और ऐसे संदाय के व्यतिक्रम में रकम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन वसूली होगी और, नियंत्रक, वसूली के प्रयोजनों के लिए उक्त संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

1974 का 2

विधिमाम्य-
करण।

32. (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1971 के अधीन इसके निरसन से पूर्व की गई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई (जारी की गई किसी अधिसूचना या निदेश या निर्धारित किराए या मंजूर अनुज्ञा या किए गए आदेश सहित) वैसे ही विधिमाम्य और प्रभावी समझी जाएगी, मानों कि उक्त अधिनियम और उक्त अधिनियम में संशोधन करने वाली पश्चात्तवर्ती अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध राष्ट्रपति की अनुमति उपाप्त करने के पश्चात् ही अधिनियमित किए गए थे, और उक्त अधिनियम ऐसे सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त रहा था जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

1971 का 23

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात, किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के किसी उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराएगी जो हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1971 के अधीन अपराध नहीं था और जो नियत दिन से पूर्व हुआ था।

1971 का 23

नियम बनाने
की शक्ति।

33. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) नियम बनाते समय सरकार, यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन जुर्माने में, जो 500 रुपए तक का हो सकेगा और जब उल्लंघन निरन्तर हो तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

निरमन और
व्यावृत्तियां।

34. (1) हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1971 का एतद्द्वारा निरमन किया जाना है।

(2) ऐसे निरमन के होते हुए भी, किन्तु उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन को उक्त अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित सभी वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का, निष्पादन कार्यवाही सहित, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटान किया जाएगा, मानो कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध सुसंगत समय प्रवृत्त थे।

(3) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय या प्राधिकरण या अधिकरण को किसी ऐसे वाद या कार्यवाही को पुनः चालू करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, जिसमें पारित आदेश पहले ही अन्तिम और निष्पादित हो चुके हैं।

35. (1) हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियंत्रण अध्यादेश, 1987 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

1987 के
हिमाचल
प्रदेश
अध्यादेश
सं 5 का
निरसन।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त हो गया था जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची-I

[धारा 2 का खण्ड (अ) देखें]

1. पति-पत्नी,
2. पुत्र,
3. पुत्री,
4. माता,
5. पिता,
6. पूर्वमृत पुत्र की विधवा,
7. पूर्वमृत पुत्र का पुत्र,
8. पूर्वमृत पुत्र की पुत्री।

अनुसूची-II

(धारा 16 देखें)

धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) और धारा 15 के अधीन वास्तविक अपेक्षा के आधार पर परिसर के कब्जे की वापसी के मामले में समन का प्रारूप।

सेवा में

.....
.....
(किराएदार का नाम, विवरण और निवास स्थान)

जब कि श्री ने धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) या धारा 15 में विनिर्दिष्ट आधार पर (यहां परिसर का विवरण अन्तःस्थापित करें) से आपकी बेदखली के लिए आवेदन दिया है (जिस की प्रति संलग्न है);

आपको एतद्द्वारा इसकी तामील से पंद्रह दिनों के भीतर नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने के लिए और पूर्वोक्त आधार पर किए गए बेदखली के आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए नियंत्रक की अनुमति अभिप्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है जिसके व्यतिक्रम में, उक्त पंद्रह दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी भी समय, आवेदक कथित परिसर से आपकी बेदखली का आदेश अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

व्यवस्थित होने और आवेदन का प्रतिवाद करने के लिए अनुमति, धारा 16 की उप-धारा (5) में यथा निर्दिष्ट शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन द्वारा नियंत्रक से अभिप्राप्त की जा सकेगी।

आज.....को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

नियंत्रक।

शिमला-171002, 20 अक्तूबर, 1987

संख्यांक एल0 एल0 आर0 डी (6) 21/87 लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 24 सितम्बर, 1987 के हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक में प्रकाशित, राष्ट्रपति महोदय द्वारा यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0 21) के प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ को जन साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Lokayukta (Dvitiya Sanshodhan) Act, 1987 (Act No. 21 of 1987) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Act No. 21 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (SECOND AMENDMENT) ACT, 1987

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 19TH SEPTEMBER, 1987)

AN

ACT

Further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Second Amendment) Act, 1987.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 21st day of July, 1987.

2. Sub-section (3) of section 11 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act) shall be omitted.

Amendment of section 11.

3. After section 11 of the principal Act, the following new section 11-A, alongwith its heading, shall be added, namely:—

Insertion of new section 11-A.

“11-A. **Power to punish for contempt.**—The Lokayukta shall have, and exercise the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as a High Court has and may exercise and, for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall have effect subject to the modifications that—

- (a) the references therein, to a High Court shall be construed as including a reference to the Lokayukta;
- (b) sub-section (1) of section 18 shall not apply to the Lokayukta; and
- (c) in proviso to sub-section (1) of section 19 a reference to “Judicial Commissioner in any Union territory” shall be construed as including a reference to the Lokayukta.”

4. In the Second Schedule to the principal Act, with effect from 1st April, 1986, for the word and figures “Rs. 4,000”, the figures and word “9,000 rupees” shall be substituted.

Amendment of Second Schedule.

5. (1) The Himachal Pradesh Lokayukta (Second Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on the day on which such thing was done or action was taken.

17 of 1983

70 of 1971

1 43 of 1987

शिमला-2, 20 अक्टूबर, 1987

संख्या एल. एल. आर. (डी) (6) 27/87-लैजिस्लेशन.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 अक्टूबर, 1987 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1987 (1987 का विधेयक संख्यांक-19) को वर्ष 1987 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

1987 का अधिनियम संख्यांक 24.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1987

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 अक्तूबर, 1987 को यथा अनुमोदित)

31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, संक्षिप्त नाम । 1987 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धन-राशियाँ, जिनका योग 36,55,37,543 रुपये (छत्तीस करोड़, पचपन लाख, सैंतीस हजार, पांच सौ तैंतालीस रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएँ जिनका वित्तीय वर्ष 1987-88 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए 36,55,37,543 रुपये की और राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3		
भाग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनुधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
3	न्याय प्रशासन (राजस्व)	8,62,000	—	8,62,000
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	88,57,000	—	88,57,000
5	भू-राजस्व (राजस्व)	7,03,70,000	—	7,03,70,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	4,75,000	—	4,75,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति (राजस्व)	1,36,50,000	—	1,36,50,000
	(पूंजी)	7,50,000	—	7,50,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण (राजस्व)	—	1,82,728	1,82,728
	(पूंजी)	—	1,000	1,000
10	लोक निर्माण (राजस्व)	23,57,000	—	23,57,000
	(पूंजी)	34,05,000	2,97,435	37,02,435
11	कृषि (राजस्व)	6,18,50,000	3,350	6,18,53,350
	(पूंजी)	20,00,000	—	20,00,000
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (राजस्व)	33,00,000	—	33,00,000
	(पूंजी)	—	41,717	41,717
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	55,50,000	1,39,153	56,89,153
	(पूंजी)	10,00,000	—	10,00,000
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	5,19,69,000	4,50,000	5,24,19,000
	(पूंजी)	1,56,45,240	45,50,000	2,01,95,240
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	26,300	5,258	31,558
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण (राजस्व)	1,11,21,000	—	1,11,21,000
	(पोषाहार सहित) (पूंजी)	11,04,000	—	11,04,000
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	5,00,70,000	20,000	5,00,90,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	18,00,000	—	18,00,000
27	श्रम और रोजगार (पूंजी)	—	2,02,975	2,02,975
28	जल आपूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व)	56,57,000	—	56,57,000
	(पूंजी)	3,22,05,000	11,62,323	3,33,67,323
29	वित्त (राजस्व)	—	15,614	15,614
	(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
31	जन-जातीय विकास			
	(राजस्व)	84,70,400	21,050	84,91,450
	(पूजा)	9,50,000	—	9,50,000
	जोड़	35,84,43,940	70,93,603	36,55,37,543
	(राजस्व)	29,63,84,700	8,37,153	29,72,21,853
	(पूजा)	6,20,59,240	62,56,450	6,83,15,690

[Authoritative English text of Himachal Pradesh Vinayog (Sankhya 4) Adhiniyam, 1987 (1987 ka Adhiniyam Sankhyank 24) as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Act No. 24 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) ACT, 1987

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH OCTOBER, 1987)

AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1988.

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1987.

Issue of a further sum of Rs. 36,55,37,543 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 36,55,37,543 (Thirty six crores, fifty-five lakhs, thirty-seven thousand, five hundred and forty three rupees) towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year 1987-88 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Demand No.	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legisla- tive Assem- bly	Charged on the Consoli- dated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
3	Administration of Justice (Revenue)	8,62,000	—	8,62,000
4	General Administration (Revenue)	88,57,000	—	88,57,000
5	Land Revenue (Revenue)	7,03,70,000	—	7,03,70,000
7	Police and Allied Organisations (Revenue)	4,75,000	—	4,75,000
8	Education, Sports and Arts and Culture (Revenue)	1,36,50,000	—	1,36,50,000
	(Capital)	7,50,000	—	7,50,000
9	Health and Family Welfare (Revenue)	—	1,82,728	1,82,728
	(Capital)	—	1,000	1,000
10	Public Works (Revenue)	23,57,000	—	23,57,000
	(Capital)	34,05,000	2,97,435	37,02,435
11	Agriculture (Revenue)	6,18,50,000	3,350	6,18,53,350
	(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
12	Irrigation and Flood Control (Revenue)	33,00,000	—	33,00,000
	(Capital)	—	41,717	41,717
16	Forest and Wild Life (Revenue)	55,50,000	1,39,153	56,89,153
	(Capital)	10,00,000	—	10,00,000
17	Roads and Bridges (Revenue)	5,19,69,000	4,50,000	5,24,19,000
	(Capital)	1,56,45,240	45,50,000	2,01,95,240
18	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)	26,300	5,258	31,558
19	Social Security, Welfare (Revenue)	1,11,21,000	—	1,11,21,000
	(including nutrition) (Capital)	11,04,000	—	11,04,000
20	Rural Development (Revenue)	5,00,70,000	20,000	5,00,90,000
23	Water and Power Development (Revenue)	18,00,000	—	18,00,000
27	Labour and Employment (Capital)	—	2,03,975	2,03,975
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	56,57,000	—	56,57,000
	(Capital)	3,22,05,000	11,62,323	3,33,67,323
29	Finance (Revenue)	—	15,614	15,614
	(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
31	Tribal Development (Revenue)	84,70,400	21,050	84,91,450
	(Capital)	9,50,000	—	9,50,000
	Total ...	35,84,43,940	70,93,603	36,55,37,543
	(Revenue)	29,63,84,700	8,37,153	29,72,21,853
	(Capital)	6,20,59,240	62,56,450	6,83,15,690

